चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन रीटेल चेन गोम भारत में रखेगी कदम

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। चीन की सबसे बड़ी कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन रीटेल चेन गोम ग्लोबल एक्सपैंशन प्लान के तहत सबसे पहले भारत में कदम रखने जा रही है। इंडस्ट्री के दो सीनियर एग्जिक्युटिव ने बताया कि करीब 11 अरब डॉलर (लगभग 763 अरब रुपए) की कंपनी भारत में अपने खुद के ब्रैंड के स्मार्टफोन, टेलिविजन और इलेक्ट्रिक अप्लायंस लॉन्च करेगी, जो प्राइस के मामले में शाओमी, सैमसंग, टीसीएल और ओपो के साथ आक्रामक रूप से मुकाबला करेंगे।

भारत में करेगी बड़ा निवेश: हॉन्ग कॉन्ग एक्सचेंज पर लिस्टेड गोम रीटेल होल्डिंग्स के चीन में 1,700 से ज्यादा स्टोर्स हैं। पीयूष पुरी को गोम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का हेड बनाया गया है। पुरी इससे पहले फॉक्सकॉन इंडिया के इन-हाउस ब्रैंड, इनफोकस को संभाल रहे थे। चीन के दूसरे ब्रैंड्स की तरह ही गोम भी भारत में ब्रैंड को जमाने के लिए भारी निवेश करेगी। कंपनी आगामी फेस्टिव सीजन में 10,000 रुपए के सेगमेंट में अपने 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इन्हें ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स दोनों के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी इसके बाद फ्लिपकार्ट के जरिए टेलिविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और किचन अप्लायंस लॉन्च करेगी।

लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट: गोम भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना चाहती है। वह देश में बेचने के लिए सारे प्रॉडक्ट्स यहीं बनाना चाहती है। इससे कंपनी को इंपोर्ट ड्यूटी के असर से बचने में मदद मिलेगी। एक एग्जिक्युटिव ने बताया, गोम ने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। इनमें अपना प्लांट लगाने से लेकर किसी अन्य से प्लांट खरीदने जैसे ऑप्शंस भी शामिल हैं। वह रिलायंस जियो समेत कई इंडियन ब्रैंड्स के लिए पहले से मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है।

टेक्सास गवर्नर ने भारत, अमेरिका के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों की वकालत की

ह्यूस्टन 13 अगस्त (ए)। अमेरिका के टेक्सॉस राज्य के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भारत और टेक्सॉस के बीच ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत व्यापारिक संबंध जरूरी है। उन्होंने कहा कि टेक्सास और भारत के बीच आर्थिक स्तर पर जुड़ाव दोनों पक्षों के लिए बेहद फायदेमंद होगा।

एबॉट ने शनिवार को इंडो-अमेरिकन चेम्बर ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन (आईएसीजीएच) के 19वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। गवर्नर ने कहा, हम साथ काम करके आर्थिक अवसरों का विस्तार करना जारी रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि टेक्सास नौकरी तलाशने और कारोबार शुरू करने के लिए सर्वोत्तम स्थान बना रहे। उन्होंने कहा कि 19 वर्षों से आईएसीजीएच ह्यूस्टन में छोटे कारोबारियों को मदद कर रहा है और अगली पीढ़ी के उद्यमियों और कारोबारी दिग्गज को प्रेरित कर रहा है। चेंबर के साथ हमारे संबंधों से भारत और टेक्सास के बीच साझेदारी और मजबूत होगी।

एबॉट ने कहा कि भारत को माल निर्यात करने वाला टेक्सास दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारतीय उत्पादों का आयात करने वाला चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत के लिए वैश्विक निवेश के लिहाज से टेक्सास सबसे प्रमुख स्थान बन गया है। टैक्सास को एक बेहतर निवेश स्थल के तौर पर प्रचारित करने के लिए भारत की नौ दिवसीय यात्रा के बारे में एबॉट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनकी यह आशा और मजबूत हुई है कि टेक्सास-भारत संबंधों को काफी आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने महिंद्रा का उत्तरी अमेरिका का मुख्यालय टेक्सास में स्थापित करने और पिछले साल हरिकेन चक्रवात के दौरान मदद के लिए 15 लाख डॉलर देने पर कंपनी का धन्यवाद किया।

चौथी तिमाही में बैंकों में पूंजी डालेगी सरकार

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का अंतिम चरण इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में हो सकता है। केंद्र ने 21 सरकारी बैंकों के लिए 30 सूत्री एक एजेंडा बनाया है जिसे ईज (एनहांस्ड एक्सेस ऐंड सर्विस एक्सीलेंस) नाम दिया गया है। पहली बार बैंकों को इस एजेंडे के क्रियान्वयन में उनके प्रदर्शन के आधार पर पैसों का आवंटन किया जाएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इस एजेंडे के अनुपालन में बैंकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का जिम्मा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को सौंपा है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीसीजी को दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र यह तय करेगा कि किस बैंक को इस वित्त वर्ष में कितना पैसा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और सभी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि आईबीए ने इस वर्ष मई में बोली आमंत्रित की थी और बीसीजी ने सबसे कम बोली लगाई थी। केंद्र सरकार इस साल पहले ही पंजाब नैशनल, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक में 113 अरब रुपए निवेश कर चुकी है लेकिन इसका मकसद इन पांच बैंकों को नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना था। फंसे कर्ज की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल उनमें 2.11 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी।

सरकार इन बैंकों में 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और बाकी राशि उन्हें खुद ही बाजार से जुटानी होगी। पुनर्पूंजीकरण के पहले चरण की रूपरेखा इस वर्ष जनवरी में घोषित की गई थी। इसके तहत वर्ष 2017-18 के लिए 881 अरब रुपए की राशि घोषित की गई। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने कहा था कि 2018-19 में बैंकों को 650 अरब रुपए ईज कार्यक्रम के अनुपालन में उनके प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे। सभी सरकारी बैंकों ने ईज को लागू करने के लिए अपने बोर्डों से मंजूरी ले ली है। बीसीजी को इस एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर बैंकों का मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन करने को कहा गया है।

दिवाली से पहले लॉन्च होगा जियो ब्रॉडबैंड

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। रिलायंस जियो बड़े पैमाने पर बाजार को कवर करने के लिए करीब 500 रुपए में एक हाई-स्पीड इंटरनेट आधारित टेलीविजन प्रोग्रामिंग के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सर्विस की कीमत प्रति माह 500 रुपए होगी।

दिवाली से पहले लॉन्च होगी सर्विस: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो दिवाली (7 नवंबर) से पहले जियो गिगाफाइबर को लॉन्च कर सकती है। शुरू में यह सर्विस मेट्रो शहरों में लॉन्च की जाएगी जहां मांग अधिक है। सर्विस की उपलब्धता 15 अगस्त से पंजीकरण शुरू होने की संख्या पर निर्भर करेगी, यानी जिस क्षेत्र में अधिकतम संख्या में लोग पंजीकृत होंगे, वहां सर्विस पहले मिल जाएगी।

जियो का पैक होगा सस्ता : केबल ऑपरेटरों के ब्रॉडबैंड पैक की तुलना में जियो पैक लगभग आधा सस्ता होगा।केबल ऑपरेटरों द्वारा दिए जा रहे होम ब्रॉडबैंड पैक काफी महंगे हैं। मौजूदा समय में 100 जीबी डेटा पैक के लिए 700 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक प्रति माह शुल्क लिया जा रहा है जबकि टीवी सेवाओं के लिए 250-300 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। जियो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट टीवी का मजा एक ही पैक में देने जा रहा है।जियो का लक्ष्य सस्ती सर्विस के साथ अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करना है। विश्लेषकों का मानना है कि जियो को ब्रॉडबैंड सर्विस 4जी मोबाइल ब्रॉडबैंड से भी सस्ती होगी।

थाली से गायब हुई सब्जियां

सोलन 13 अगस्त (ए)। प्रदेश में बाहरी राज्यों से सप्लाई कम होने से सब्जियों के रेट में भारी इजाफा हुआ है। मटर सहित कई सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी यदि मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहा तो सब्जियों के रेट में काफी अधिक इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार पंजाब, हरियाणा व यू.पी. सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों की नकदी फसलों को काफी अधिक नुक्सान हुआ है। इस कारण बाहरी राज्यों की सब्जियां हिमाचल की मंडियों में नहीं पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि सब्जियों की सप्लाई में इन दिनों 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। हिमाचल में औसतन 20,000 टन सब्जियां व फल आदि की सप्लाई बाहरी राज्यों से होती है लेकिन गत कुछ दिनों से 8000 से 10,000 टन सब्जियों भी मंडियों में नहीं पहुंच रही हैं। लौकी को छोड़कर सभी सब्जियों के दाम 2 से 4 गुना तक बढ़ गए। पत्ता गोभी, बैंगन, ग्वारफली, कद्दू, प्याज, आलू, भिंडी, कटहल, फूलगोभी, टमाटर, हरी मिर्च के भाव में भी काफी तेजी आई है। इन दिनों बाहरी राज्यों से सब्जियों की सप्लाई कम आ रही है। इसकी वजह से सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। हिमाचल में भी इन दिनों सब्जियों का उत्पादन कम होता है, जिस कारण भी रेट बढ़ रहा है।

गोल्ड पॉलिसी बनाने के लिए सरकार ने बढ़ाया कदम, बनाई अस्थायी कमेटी

मुंबई 13 अगस्त (ए)। सरकार ने व्यापक गोल्ड पॉलिसी तैयार करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। उसने एक दर्जन इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स की अस्थायी कमेटी बनाई है, जो वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के सुझाव के मुताबिक गोल्ड और जूलरी के लिए डोमेस्टिक कांउसिल का स्ट्रक्चर तय करेगी। इस कांउसिल का सबसे अनूठा हिस्सा हैंडमेड और कस्टमाइज्ड आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सबसे छोटे साझीदारों-कारीगरों और सुनार से लेकर सबसे बड़े स्टेकहोल्डर्स-जूलर और बुलियन डीलर का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होगा, जिससे नौकरियों के ज्यादा मौके बनेंगे। पिछले गुरुवार को इंडिया इंटरनैशनल जूलरी शो मुंबई में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित प्रभु ने कहा था, हम भारत में पहली बार एक गोल्ड कांउसिल बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि गोल्ड एक कमोडिटी बने, जिसका वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जा सके। हमारे पास करीब हरेक गांव में जूलर हैं। वे कस्टमाइज्ड जूलरी बना सकते हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश : उनका कहना था, हमारे पास हैंडमेड जूलरी बनाने वाले सुनार हैं। इस बात की कल्पना कोजिए कि कस्टमाइज्ड और हैंडमेड जूलरी के लिए ग्लोबल मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनसे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डोमेस्टिक गोल्ड कांउसिल बनाने के अलावा हम निर्यात को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक रणनीति भी बनाई है।

सूत्रों के अनुसार कमेटी में इंडिया बुलियन ऐंड जूलर्स असोसिएशन (आईबीजेए), जेम ऐंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल (जीजेईपीसी), भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी), तमिलनाडु जूलर्स फेडरेशन और इंडिया जूलर्स फोरम का प्रतिनिधित्व रहेगा। इंडस्ट्री सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा ऑल इंडिया जेम ऐंड जूलरी डोमेस्टिक कांउसिल (जीजेसी) और रिफाइनरीज के असोसिएशन भी कमेटी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। जीजेईपीसी के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल ने बताया था कि उन्हें कमेटी की मेंबरशिप के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि एक-दो दिन में इसके बारे में पता चल जाएगा।

एलएंडटी कंस्ट्रक्शन को 3,028 करोड़ रु. का ठेका

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की निर्माण शाखा एलएंडटी कंस्ट्रक्शन को घरेलू बाजार में 3,028 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। कंपनी ने आज यह जानकारी दी। एलएंडटी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि एलएंडटी कंस्ट्रक्शन की इमारत एवं कारखाना कारोबार को जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (जीएचआईएएल) से 3,028 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण (ईपीसी) ठेका हासिल हुआ है। कंपनी ने कहा कि यह ठेका हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टिमनल की इमारत के विस्तार और एयरसाइड (हवाई अड्डे में पासपोर्ट, सीमा शुल्क और सुरक्षा जांच वाला क्षेत्र) बुनियादी ढांचे से जुड़ा है।

बिकने की राह पर है कॉम्प्लान, विप्रो-आईटीसी-कैडिला लगा सकते हैं बोली!

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन द्वारा हॉर्लिक्स का कारोबार बेचने की कवायद शुरू करने के बाद क्राफ्ट हेनज भी अपने कॉम्प्लान के व्यवसाय को बेचने जा रहा है।खबरों के अनुसार आई.टी.सी. लिमिटेड, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग लिमिटेड और कैडेला हेल्थकेयर लिमिटेड भारत के लोकप्रिय पोषण पेय ब्रांड कॉम्प्लान को खरीदने की दौड़ में हैं। जल्द ही वे इस बोली के लिए पेशकश कर सकते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार तीनों बोलीदाता 15 सितंबर तक बोली जमा कर सकते हैं। क्राफ्ट हेनज द्वारा कंपनी कॉम्प्लान को बेचने की योजना तब सामने आई, जब हाल ही में उसके प्रतिद्वंद्वी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन (जी.एस.के.) ने हॉर्लिक्स को बेचने की प्रक्रिया शुरू की। भारत के 5000 करोड़ रुपए के पोषण पेय बाजार में कॉम्प्लान की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी है। बाजार में कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स के अलावा कैडबरी के बोर्नविटा और जी.एस.के. के बूस्ट का दबदबा है।

हालांकि यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के मुताबिक हॉर्लिक्स और बोर्नविटा की वृद्धि 2017 में 8.6 फीसदी रही, जो 2014 में 13.2 फीसदी थी। पिछले कुछ वर्षों में कई नए खिलाड़ियों ने इस बाजार में कदम रखा है, जिससे प्रमुख ब्रांडों को बड़ी चुनौती मिली है। क्राफ्ट हेनज के कॉम्प्लान कारोबार को खरीदने के बारे में आई.टी.सी., विप्रो और कैडेला की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्टों के अनुसारजू लाई में विप्रो, आई.टी.सी., कैडेला और ऐबॉट कॉम्प्लान का कारोबार खरीदने के लिए क्राफ्ट हेनज के संपर्क में थे।

जीएसटी कटौती का फायदा नहीं देने पर KFC, Pizza Hut को नोटिस

नई दिल्ली 13 अगस्त (ए)। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद की ओर से टैक्स में कटौती के बाद ग्राहकों को फायदा नहीं देने पर नैशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (एनएपीए) ने जांच शुरू की है। एनएपीए ने रेस्ट्रॉन्ट चेन्स सबवे, पिज्जा हट और केएफसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनएपीए ने नोटिस में टैक्स में कमी का फायदा ग्राहकों को न देने को लेकर सवाल पूछा है।

ये है मामला: जीएसटी कांउसिल ने नवंबर 2017 में रेस्ट्रॉन्ट्स पर रेट्स में कटौती की थी। एयर-कंडीशंड रेस्ट्रॉन्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और नॉन-एयरकंडीशंड पर 12 फीसदी किया गया था। बहुत सी रेस्ट्रॉन्ट कंपनियों ने इसके बाद मेन्यू में सभी आइटम्स पर प्राइसेज नहीं घटाए थे क्योंकि जीएसटी में कमी से साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस ले लिया गया था। रेस्ट्रॉन्ट कंपनियों का कहना है कि इससे उनके प्रॉफिट पर असर पड़ा है और प्राइस में कटौती करने की उनकी क्षमता कम हो गई है।

कंपनियों ने कहा करेंगे पूरा सहयोग: पिज्जा हट की मालिक यम रेस्ट्रॉन्ट्स और सबवे ने एनएपीए की ओर से प्रश्न पूछे जाने की पुष्टि की है। पिज्जा हट और केएफसी की मालिक यम इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, हम किसी भी प्रश्न को लेकर अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे। हम अथॉरिटीज की ओर से अधिक जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सबवे के प्रवक्ता का कहना था, सबवे इस जांच में एनएपीए के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है। सबवे देश में 630 रेस्ट्रॉन्ट ऑपरेट करती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के मालिकाना हक वाली डॉमिनोज पिज्जा की भी इसी तरह की जांच चल रही है। रेस्ट्रॉन्ट चेन्स 30 रुपए से अधिक की एंट्री-लेवल प्राइसिंग के साथ वैल्यू बढ़ा रही हैं। इन चेन्स ने कुछ ही प्रॉडक्ट्स के प्राइसेज घटाए हैं। कम प्राइस वाले आइटम्स को सस्ता किया गया है, जबकि प्रीमियम डिशेज महंगी हो गई हैं। रेस्ट्रॉन्ट चेन्स का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर 10-18 फीसदी का असर पड़ा है।

भूषण पावर के लिए टाटा-जेएसडब्ल्यू में खींचतान, लौह अयस्क तक पहुंची आंच

कोलकाता 13 अगस्त (ए)। भूषण पावर ऐंड स्टील के अधिग्रहण को लेकर देश की दो प्रमुख स्टील कंपनियों- टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की लड़ाई की आंच अब लौह अयस्क तक पहुंचती दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने ओडिशा में लौह अयस्क की नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी है। खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक खदान वाली कंपनियों की प्रतिभागिता के इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही है। उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को सुंदरगढ़ जिले के दो लौह अयस्क ब्लॉकों - चांदीपोशी और पूरहीबहल की नीलामी पर रोक लगा दी। इसकी नीलामी 5 और 8 मई को होनी थी।

जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील सहित 17 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि एमएमडीआर प्रावधान से प्रभावित होने वाली एकमात्र कंपनी टाटा स्टील हो सकती है क्योंकि नियमों के तहत अगर किसी कंपनी ने 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पहले से ही खदान पट्टे पर लिया हुआ हो तो वह इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती है। मामला न्यायालय में लंबित होने का हवाला देकर टाटा स्टील के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील का पक्ष जानने के लिए ई-मेल किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समझा जाता है कि टाटा स्टील के पास राज्य में 6 लौह अयस्क और मैंगनीज खदान हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 50 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि ओडिशा सरकार ने 10 वर्ग किलोमीटर की सीमा को बढ़ाकर 75 वर्ग किलोमीटर करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है।

जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के बीच खनिज को लेकर एक और जंग छिड़ गई है। दोनों कंपनियों ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत भूषण स्टील को लेकर भी प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन इसमें बाजी टाटा स्टील के हाथ लगी। अब जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील भूषण पावर ऐंड स्टील को लेकर एक-दूसरे के सामने है।

यह सौदा जिसके भी खाते में जाएगा वह कम से कम अल्पावधि के लिए घरेलू स्टील बाजार में नंबर एक कंपनी बन सकती है।